श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं मद संख्या 10 के अन्तर्गत अगले सप्ताह के लिये निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं—

सातवीं पांच वर्षीय योजना के प्रारूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को मिल रहे आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। यह न सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्गों के हित के विपरीत है बल्कि संविधान के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति देश की कुल आबादी का एक चौथाई है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या अभी भी नगण्य है। अभी भी देश में जातिगत आधार पर छुआछूत मौजूद है। उन पर अत्याचार घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण के लिए प्रति दस वर्षों के बाद अवधि बढ़ाने के लिये संसद की अनुमति का प्रावधान रखा था लेकिन सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अवधि की सीमा नहीं रखी थी। संविधान के अनुसार आरक्षण का आधार सामाजिक तथा शैक्षणिक होगा। संविधान ने कहीं भी आर्थिक आधार की बात नहीं कही है।

अतः सरकार का यह सुझाव संविधान विरोधी है। सरकार इसे तत्काल वापस ले और सदन में इस पर चर्चा कराई जाय।

SHRI MALLIKARJUN : Hon'ble Members have raised certain matters to be discussed during the next week. I think, it is not possible to do so because under rule 289 I have already laid the report of the BAC and no matter whatever can be discussed without the consent of the BAC. These things may be brought before the BAC through their respective Members in the Committee.

14-46 hrs.

STATEMENT *re* : EXTENSION OF TIME FOR COMPLETION OF THE INQUIRY AND SUBMISSION OF REPORT BY THE KUDAL COMMISSION OF INQUIRY ON GANDHI PEACE FOUNDATION AND OTHER ORGANISATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) ; Consequent on the adoption of a Resolution by the House on 28th August' 1981 a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice P.D. Kudal was set up by Notification dated 17th February, 1982. Copies of the Notification were laid on the Table of the House on 3rd March, 1982. The Commission was required to complete its inquiry and submit a report to the Central Government on or before 31st July, 1982.

On the request of the Commission, the time for the submission of the report was extended twice, upto 31st July, 1983 and then upto 31st July, 1984. The Chairman of the Commission of Inquiry had requested the Government for extending the time for the submission of the report by one more year. The Government had considered this request and the term of the Kudal Commission of Inquiry on Gandhi Peace Foundation and other organisations was accordingly being extended upto 31st July, 1985.

14.48 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I have given a notice under rule 193. I want a discussion on this. My contention is that those organisations and individuals who are connected with late Jayaprakash Narayan, the Government is trying to pull them before the

[Prof. Madhu Dandavate]

Kudal Commission. They have extended the time twice. They want to extend the time again. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a *suo motu* statement made by the Minister.

PROF. MADHU DANDAVATE : I have given notice under rule 193 I want to know whether the Government is going to allow a discussion on this. They want to destroy all organisations which are connected with late Jayaprakash Narayan. We are not going to tolerate this. They are destroying the spirit of Gandhian philosophy in the country. We would like to know whether the Government will bring a discussion on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will be considered in the BAC meeting on Monday.

PROF. MADHU DANDAVATE : What is your assurance ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : This will be taken up in the BAC meeting. Now legislative business Shri Harinatha Misra. (*Interruptions*) When the Chair gives a decision, I do not want the hon. Members that they should obey the Chair, but at least they should listen to the reply. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE : We accept your proposal. Please communicate our feeling that it should be taken by up by the BAC.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL, 1982

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI HARINATHA MISRA) : Sir, I beg to move for leave to withdraw a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1984.

MR. DEPUTY SPEAKER : Yes, Prof. Ajit Mehta, you want to oppose the withdrawal.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भू-अर्जन कानून के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। मंत्री महोदय, विधेयक लेकर के सदन में आए तो मैंने यह सोचा था कि जो खामियां हैं और भू-अर्जन से जो घाटा होता है, उस की क्षति-पूर्ति का प्रावधान किया जायेगा। लेकिन बिल को देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई। बिल में प्रावधान है कि नोटिस देने के बाद दो वर्ष के अन्दर ही निपटारा हो जायेगा। लेकिन दो वर्ष भी निपटारा होने में लग सकते हैं। नोटिस आज दिया जाए और जमीन का अधिग्रहण दो वर्ष के बाद हो तो दो वर्ष के बाद की कीमत ही किसान को मिलनी चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : विधेयक में 1984 के पहले जो नोटिस दिया जा चुका है, उसको भी आप दो साल का समय देने जा रहे हैं। जिनको आज नोटिस दिया जा रहा है, उनको भी दो साल और 1984 से पहले जो नोटिस दिया हुआ है, उनको भी दो साल का समय आप दे रहे है ? नोटिस देने के बाद जो बाजार भाव होगा, उस पर ही भुगतान होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिलने के बाद अगर किसान कोर्ट में जाता है और हो सकता है कि उसके पक्ष में फैसला हो जाए, लेकिन बिल में यह प्रावधान है कि कोर्ट में जब तक मामला रहेगा तो उस अवधि का ब्याज उसको नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं, यह किसान के साथ अन्याय है। आप जानते हैं कि दिल्ली में